Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 08-12-2006
Participants : Singh Shri Dushyant,Bhargav Shri Girdhari Lal

an>

Title: Need to bring ten more districts of Rajasthan under National Rural Employment Guarantee Programme.

अध्यक्ष महोदय,मैं बहुत छोटी सी बात कहने जा रहा हूं। ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम**:श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर)** राजस्थान के कुल छः जिलों में प्रारंभ की गई है। राजस्थान सबसे गरीब प्रदेश है।

अध्यक्ष महोदय : यह छोटी नहीं, बहुत अहम बात है।

राजस्थान में इसके अंतर्गत प्रथम चरण में देश के लगभग 600 जिलों में से 200 जिले शामिल किए**: श्री गिरधारी लाल भार्गव** गए हैं। राजस्थान की जनसंख्या अधिक नहीं है। राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिक है और प्रति जनता को हर प्रकार की परिस्थिति मेंव्यक्ति आय कम है। वहां कृाि उत्पादन भी कम है, कृाि मजदूरी भी कम है। राजस्थान में हिंदुस्तान का केवल एक परसेंट पानी उपलब्ध होता है। राजस्थान की स्थिति अजीब प्रकार की है, आज भी पश्चिम राजस्थान के सब जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं। बाड़मेर और जैसलमेर में बाढ़ आई हुई है। राजस्थान में और जिले भी समस्याग्रस्त हैं। वहां पानी को निकालने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास कर लिया है लेकिन राज्य सरकार के प्रयास

करने के बाद भी पानी निकल नहीं पाया है।

इतनी बात कहनी है कि उन्होंने और प्रांतों के साथ न्याय किया है। राज्य में अनुसूचित जाति, मुझे माननीय मंत्री जी से जनजाति की जनसंख्या 29.8 प्रतिशत है जबकि आंध्र प्रदेश एवं महाराट्र में यह अनुपात क्रमशः 22.8 प्रतिशत एवं 19.1 प्रतिशत है। राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय 2003-04 में 15.485 रुपया थी जबकि आंध्र प्रदेश एवं महाराट्र की प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः 20,757 रुपया तथा 29,204 रुपया थी। इसके बावजूद भी जहां राजस्थान के 32 जिलों में से मात्र 6 जिलों का ही इस योजना के प्रथम चरण में चयन किया गया है। आंध्र प्रदेश के 23 में से 13 जिले इसके अंतर्गत लिए गए हैं और महाराट्र के 35

में से 12 जिले लिए गए हैं जबकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृटि से बहुत बड़ा क्षेत्र है।

मैं समझता हूं कि राजस्थान के सीमित जल साधन एवं विशाल रेगिस्तान क्षेत्र के कारण उद्योगों की स्थापना एवं कृाि के विस्तार की सीमित संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में जीवनयापन हेतु रोजगार की मांग अधिक है। राज्य में चयनित मात्र 6 जिलों में 12.47 लाख व्यक्तियों द्वारा रोजगार की मांग की गई है। इस प्रकार प्रति जिले 2.08 लाख रोजगार की मांग देश में स र्वाधिक है। तुलनात्मक आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में रोजगार की औसत मांग 1.63 लाख एवं महाराट्र के 12 जिलों में औसत मांग 0.33 लाख है। बिहार में जहां 38 जिलों में से 28 का इस योजना के प्रथम चरण में चयन किया गया है, प्रति जिले रोजगार की औसत मांग 0.31 लाख है। झारखण्ड के 22 जिलों में से 20 का इस योजना के प्रथम चरण में चयन किया गया है। झारखंड के प्र ाति जिला रोजगार की औसत मांग 0.32 लाख है। राज्य का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा रेगिस्तानी है, परन्तु इस क्षेत्र के एक भी जिले को इस योजना में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री मापदंड में परिवर्तन करें ताकि इसमें दस जिले और लिए जाएं, इससे सोलह जिले हो जाएंगे। माननीय मंत्री जी मापदंड में परिवर्तन करके कम से कम दस जिलों को जोड़ें ताकि राजस्थान में ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का लाभ मिल सके। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि इस योजना का विस्तार कर अतिरिक्त जिले शामिल किए जाएं। यह आवश्यक है कि कार्यक्रम के विस्तार के समय राज्य के जिलों को कार्यक्रम के उद्देश्य एवं मानदण्ड के अनुसार शामिल कर वर्तमान विसंगित को दूर किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुबह कहा है कि इसे प्लानिंग कमीशन देखेगा।

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR): Mr. Speaker, Sir, I would like to associate myself with the matter raised by Shri Girdhari Lal Bhargava.[R24]